'हिन्दुस्तान' की अगस्त 1988

कम्पूचिया में समझौते के आसार नहीं

□ शशिधर खां

कम्पूचिया समस्या का हल निकालने के लिए २५ से २८ जुलाई के बीच बोगोर (इंडोनेशिया) में संपन्न बैठक भी कोई ठोस मुद्दा सामने नहीं ला सकी और दक्षिण-पूर्व एशिया का यह विवादास्पद मसला पुनः अनिर्णीत रह गया। हालांकि इस बैठक की ओर एक ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया और गुटनिरपेक्ष देशों की आंखें टिकी थीं, क्योंकि कम्पूचिया से संबंधित सभी पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद थे। और तो और, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुहार्तो के विशेष आमंत्रण पर राजकुमार नरोत्तम सिंहनुक भी राजधानी यकर्ता पहुंच गए थे, जबकि पहले ही उन्होंने अपना जाना अनिश्चित रखा था तथा पुत्र रनरिद्ध को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजने की घोषणा कर दी थी।

२७ जुलाई को यकर्ता में राजकुमार सिंहनुक ने नौ साल से चल रही हिन्द चीन की लड़ाई खत्म करने के लिए नाम्पेन्ह (कम्पूचिया की राजधानी) में चार पार्टियों की सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि कम्पूचिया में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में ही अमन चैन लाना संभव है, मगर सबसे पहले विएतनामी सेना की वापसी जरूरी है।

कम्पूचिया के मामले में राजकुमार सिंहनुक ऐसी धुरी हैं, जिनकी उपेक्षा करके यहां सामान्य स्थिति लाने की बात सोची ही नहीं जा सकती। मगर श्री नरोत्तम सिंहनुक के प्रस्ताव हेंग समरिन सरकार को मान्य होंगे, इसकी उम्मीद कम है। उन्होंने सीधे-सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव की देखरेख में नाम्पेन्ह से तमाम विदेशी फौजों की वापसी, इस मसले पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। उनके मुताबिक जब विएतनामी कम्पूचिया से चले जाएंगे तो मौजूदा एक पार्टी प्रशासन को चार पक्षीय प्रशासन में बदल दिया जाएगा और चारों पक्षों की सेनाएं भी बरकरार रहेंगी। उन सबका एक चार पक्षीय जनरल स्टाफ होगा। कम्पूचिया पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एक पूर्णतः गुटनिरपेक्ष देश में होगा, जिसका हिन्दचीन के मामले से कोई सरोकार नहीं। उसमें संयुक्त राष्ट्र के पांचों स्थायी सदस्य, दक्षिण पूर्व एशियाई संघ के छह सदस्य, विएतनाम, लाओस, कम्पूचिया के चारों गुट जापान, भारत और आस्ट्रेलिया भाग लेंगे।

जांच दल के गठन का प्रस्ताव

इंडोनेशिया के विदेश मंत्री अली अल्बास की पहल पर विश्व अधिकारियों का एक जांच दल बनाने की बात तय हो गई जो कम्पूचिया से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करेगा। यह भी तय हो गया कि लोकतांत्रिक कम्पूचिया प्रतिरोध के पूर्व अध्यक्ष नरोत्तम सिंहनुक और हेंग समरिन सरकार के प्रधानमंत्री हुन सेन के बीच अक्तूबर में पेरिस में मुलाकात होगी। लोकतांत्रिक कम्पूचिया प्रतिरोध के अध्यक्ष पद से इस्तीफा (११ जुलाई) देने के बाद से दोनों नेताओं की वह पहली बातचीत होगी। उनकी दो बार पहले भी बातचीत हो चुकी है। ११ जुलाई को श्री सिंहनुक ने उक्त पद से इस्तीफा देकर अपने पुत्र श्री रनरिद्ध को यह पद सौंप दिया और आत्मनिर्वासन लेकर फ्रांस चले गए। बोगोर में भी उन्होंने श्री रनरिद्ध को ही प्रतिनिधि बना कर भेजा था।

बोगोर में हुनसेन और श्री रनरिद्ध के अलावा आतवायी खमेररूज नेता पोलपोट तथा खमेर लोगों के नेता सोनसान भी मौजूद थे। हालांकि बैठक में किसी पक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की मगर जो भी बातें हुई उनसे सभी पक्ष सहमत नहीं थे, क्योंकि सोनसान के बार-बार आग्रह के बावजूद संयुक्त विज्ञप्ति जारी नहीं की जा सकी। हुनसेन ने भी संतोष की सांस ली कि अच्छा भला दिसंबर तक के लिए सिरदर्द टल गया क्योंकि जांच दल उसके पहले अपनी रिपोर्ट नहीं देगा।

एसियान व गुट निरपेक्ष की बैठकें

कम्पूचिया में अनुकूल स्थिति लाने के लिए बड़े जोर-शोर से कोशिशें चल रही हैं। गुटनिरपेक्ष और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों (एसियान) की आए दिन बैठकें हो रही हैं। लगभग सारा एशिया महाद्वीप चाहता है कि जल्द-से-जल्द कम्पूचिया से विएतनामी सेना हटे, निष्पक्ष चुनाव हों और वहां शांति तथा सुव्यवस्था कायम की जा सके। संयुक्त राष्ट्र में ही अंतरराष्ट्रीय शांति सेना रखने और कम्पूचिया में स्वनिर्णय का अधिकार देने की बात कही गई है।

"कम्पूचिया में अनुकूल स्थिति लाने के लिए बड़े जोरशोर से कोशिशें चल रही हैं। गुट निरपेक्ष और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों (एसियान) की आए दिन बैठकें हो रही हैं। लगभग सारा एशिया चाहता है कि जल्द से जल्द कम्पूचिया से वियतनामी सेना हटे, निष्पक्ष चुनाव हों और वहां शांति तथा सुव्यवस्था कायम की जा सके।"

४-५ जुलाई को बैंकॉक में एसियान देशों की बैठक हुई। उस बैठक में ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाइलैंड के विदेश मंत्रियों ने विएतनामी सेना द्वारा कम्पूचिया पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा करने की निंदा की तथा नरोत्तम सिंहनुक के सुझावों का समर्थन किया। उनके मुताबिक राजकुमार सिंहनुक के बताए तरीकों से ही कोई, निदान संभव है।

उसके पहले २२ जून को हो चोमिन्ह नगर में इंडोनेशिया और विएतनाम के विदेश मंत्री भी मिले थे, जिसमें विएतनाम ने १९९० तक कम्पूचिया से अपनी ५० हजार फौज हटा लेने की बात पुनः दुहराई थी। २३ जून को ही विएतनाम के प्रधानमंत्री दो मुओई ने १९९० तक सेना वापस बुलाने के निर्णय को पुख्ता किया था, मगर अभी तक फौजों की वापसी शुरू होने की कोई सूचना नहीं है।

१५ जुलाई को गुटनिरपेक्ष देशों की नई दिल्ली में बैठक हुई। भारत, इंडोनेशिया, क्यूबा, जिंबाब्वे और विएतनाम के विदेश मंत्रियों ने तय किया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे कम्पूचिया के चारों पक्षों से मशविरा करके अपना प्रतिनिधि भेजेंगे और १० अगस्त को हवाने में यह तय किया जाएगा कि सितंबर में किस प्रकार चारों पक्षों को साथ लेकर सम्मेलन बुलाया जाए। गुटनिरपेक्ष देशों की सितंबर में होने वाली बैठक साइप्रस में होगी। बोगोर सम्मेलन से ही जिंबाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे काफी आशावान हैं।

१९४१ में राजकुमार नरोत्तम सिंहनुक ने १९ वर्ष की उम्र में तत्कालीन नूम्बोडिया के शासन की बागडोर संभाली थी। १९७० के मार्च में वे सोवियत संघ की यात्रा पर गए, उसी बीच अमेरिकी इशारे पर उनके प्रतिद्वंद्वी लोन नोल ने सत्ता हथिया ली। श्री सिंहनुक ने विएतनाम युद्ध में अमेरिका का साथ देने से इंकार कर दिया था। उसी वर्ष अक्तूबर में कंबोडिया का नाम बदल कर खमेर गणतंत्र कर दिया गया और उसके साथ ही २४ वर्षों से चली आ रही संवैधानिक राजशाही समाप्त हो गई। बहुत समय बाद दुनिया को दिखाने के लिए राजकुमार सिंहनुक को पुनः सम्राट बना कर उन्हें अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया, जिससे चिढ़ कर एक साल के अंदर उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार सिंहनुक के साथ चीन की सहानुभूति थी मगर पोलपोट जैसी नहीं। इसलिए चीन की जानकारी में ही पोलपोर सरकार ने अब तक के सारी तानाशाही परंपराओं को तोड़ कर २० लाख से भी अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। राजकुमार सिंहनुक के सगे-संबंधियों को पोलपोर ने चुन-चुन कर मार डाला। उन्हें चीन की ओर से बख्श दिया गया। उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यह था कि कम्पूचिया के मामले में सोवियत संघ और अमेरिका की एक न चलने दी जाए, क्योंकि बाद में अमेरिकी बेरुखी की वजह से ही लोनर्नाल का पतन हुआ था।

परिवर्तनों का सिलसिला

१९७५ के बाद से इस क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण में बड़े बुनियादी परिवर्तन हुए। उस वर्ष ज्यों ही विएतनाम का एकीकरण हुआ कि चीन से उनके संबंध बिगड़ गए, क्योंकि विएतनाम की पीठ पर सोवियत संघ का हाथ था। चीन के कहने पर पोलपोर ने विएतनाम की दक्षिण पश्चिम सीमाओं पर उपद्रव मचाना शुरू किया। उधर उत्तरी सीमा पर विएतनाम चीन से उलझ रहा था। आखिरकार ३१ दिसंबर, १९७७ को कम्पूचिया ने विएतनाम से कूटनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी और उसके एक वर्ष बाद २५ दिसंबर, १९७८ को विएतनाम की सेना कम्पूचिया में घुस गयी। ७ जनवरी, १९७९ को पूरी तरह से नाम्पेन्ह पर विएतनाम का कब्जा हो गया। हेंग सेमरिन भी पहले पूर्वी कम्पूचिया में खमेर रुज सेना के कमांडर थे, मगर उनके अत्याचारों से चिढ़कर वे अलग हो गए थे। विएतनामी सेना की मदद से उन्हें सत्तारूढ़ होने में कामयाबी हासिल हुई और पोलपोट देश छोड़ कर थाईलैंड चले गए जहां खमेररुज छापामारों ने नई हेंग सेमरिन सरकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ रखा था।

१९७५ में ही थाईलैंड ने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध कायम किए और उसी समय से यह देश विएतनाम के खिलाफ चीन तथा अमेरिकी मुहिम का अड्डा बना हुआ है, क्योंकि कम्पूचिया को मिल रहे विएतनामी समर्थन के पीछे सोवियत संघ का हाथ है। १९८२ में थाईलैंड में ही राजकुमार सिंहनुक के नेतृत्व में निर्वासित मिलीजुली कम्पूचिया सरकार कायम की गई और तभी से हेंग सेमरिन सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश जारी है। अमेरिका ने बड़े मौके पर पैंतरा बदला और चीन के साथ मिलकर खमेर रुज छापामारों को हथियार देना शुरू कर दिया। चीन और अमेरिका प्रस्तावित कम्पूचिया सरकार में पोलपोट को भी शामिल करना चाहते हैं, मगर सिंहनुक और 'एसियान' को यह कतई पसंद नहीं। वैसे संयुक्त राष्ट्र ने भी कई उपाय सुझाए हैं, मगर यह समस्या पोलपोर को चलता किए बिना कतई नहीं सुलझ सकती जो उचित भी है।

चुनाव पर जटिल स्थिति

अब प्रश्न है कि कम्पूचिया में चुनाव हो तो कैसे हो? राजकुमार सिंहनुक का अंतरराष्ट्रीय शांति सेना का प्रस्ताव हेंग समरिन पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसी पक्ष पर ज्यादा जोर देता है। प्रधानमंत्री हुनसेन बोगोर प्रस्ताव को एक झटके से अमान्य करार देंगे, क्योंकि उन्होंने दो महीना पहले ही कह दिया था कि कम्पूचिया के मसले पर वैसे किसी गठबंधन से वे बातचीत नहीं करेंगे, जिसमें पोलपोट शामिल हो। हालांकि पोलपोट के पक्ष में तो स्वयं राजकुमार सिंहनुक भी नहीं हैं, मगर अमेरिका और चीन के दबाव के आगे वे कुछ कर नहीं पा रहे। आखिर उन्हें भी हेंग समरिन को हटाने के लिए किसी का समर्थन चाहिए। हेंग सेमरिन सरकार इस्तीफा देने के नाम पर कान पर जूं भी नहीं रेंगने देती। २९ जुलाई, १९७७ को उन्होंने सुझाव दिया था कि हेंग सेमरिन को इस्तीफा देकर एक कामचलाऊ सरकार के हाथ में सत्ता सौंप देनी चाहिए, जिसकी देखरेख में निष्पक्ष चुनाव हो सके। उसके बाद महीनों तक हुनसेन उनसे बातचीत भी करने को तैयार नहीं थे।

दूसरी ओर सोवियत संघ पर्दे के पीछे से सारी गतिविधियों पर नजर तो रखे है मगर अपनी थोड़ी भी उत्सुकता व्यक्त नहीं कर रहा। दरअसल सोवियत संघ अफगानिस्तान के नजरिए से कम्पूचिया को नहीं देख रहा, वर्ना अब तक कम्पूचिया में मौजूद ५० हजार विएतनामी सेना को वापसी शुरू हो जाती और १९९० तक के लिए इस मामले को नहीं टाला जाता।

अमेरिका और चीन भी शायद अपने खमेर रुज छापामारों को इतने ताकतवर बनाने में कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे हैं ताकि वह बलपूर्वक कम्पूचिया में सत्ता हथिया लें, वर्ना अब तक परंपरा के अनुरूप कुछ -न-कुछ परिवर्तन हो गया होता। जापान ने भी वैसे दिखाने के लिए तो १९७९ में ही विएतनाम को सहायता देना बंद कर दिया था, मगर कम्पूचिया और विएतनाम दोनों ही देशों में कई जापानी संस्थाएं काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी समझौता वार्ता कहां तक सफल हो पाएगी, कहना कठिन है।